

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 3002  
जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

.....  
हीराकुंड बांध

3002. श्री नितेश गंगा देव:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या हाल ही के वर्षों में ओडिशा राज्य में हीराकुंड बांध जलाशय की जल भंडारण क्षमता में काफी कमी कर दी गई है;
- (ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार ने हीराकुंड बांध जलाशय की गाद निकालने हेतु कोई निधि आवंटित की है; और
- (घ) यदि हां, तो आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (घ) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा संकल्पित कम्पेडियम ऑन सिल्टिंग ऑफ रिज़र्व्स इन इंडिया (2015) के अनुसार, हीराकुंड जलाशय का अंतिम बार गाद हटाने संबंधी सर्वेक्षण वर्ष 2000 में किया गया था। वर्ष 2000 के लिए उपलब्ध अंतिम गाद हटाने संबंधी सर्वेक्षण के अनुसार गाद जमा होने के कारण हीराकुंड जलाशय, जो कि वर्ष 1957 में शुरू हुआ था, की सकल क्षमता लगभग 27.27% घटी है। भंडारण क्षमता में कमी का कारण गाद जमा होना है, जो कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। सामान्यतः बड़े बांधों में गाद हटाना तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं होता है।

जल, राज्य का विषय होने के कारण गाद प्रबंधन आदि सहित प्रचालन और अनुरक्षण बांध स्वामियों द्वारा किया जाता है, जो कि सामान्यतः राज्य सरकार, केन्द्रीय/राज्य पीएसयू, निजी स्वामी होते हैं। केन्द्र सरकार विभिन्न स्कीमों जैसे बांध पुनरुद्धार और सुधार परियोजना के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

भारत सरकार ने सतत रूप में चयनित मौजूदा बांधों और संबद्ध उपस्करों की सुरक्षा और प्रचालन निष्पादन में सुधार के लिए अप्रैल, 2012 में 7 राज्यों अर्थात् मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड और उत्तराखंड में स्थित 223 बांधों के पुनरुद्धार का प्रावधान किया है। परियोजना का मूल बजट परिव्यय 2100 करोड़ रुपए था। डीआरआईपी मूलतः 6 वर्ष की अवधि का स्कीम थी। जिसके समाप्त होने की निर्धारित तिथि 30 जून, 2018 है। सितम्बर, 2018 में आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने दो वर्ष के विस्तार के साथ 3466 करोड़ रुपए सहित डीआरआईपी की लागत के संशोधन का अनुमोदन किया था।

ओडिशा सरकार ने डीआरआईपी के तहत हीराकुंड बांध को शामिल किया है। तथापि, परियोजना के तहत हीराकुंड जलाशय में गाद हटाने संबंधी कोई कार्य नहीं किया गया है। हीराकुंड जलाशय के गाद हटाने के लिए कोई निधि आवंटित नहीं की गई है।

\*\*\*\*\*